भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 550

मंगलवार, 25 जुलाई, 2023/3 श्रावण, 1945 (शक)

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन

550. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में केवल 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत तक बढ़ गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का मूल वेतन के 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाने पर भावी वेतन संशोधन किया जाना चाहिए; और

(घ) चूंकि महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दर जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक होने का अनुमान है, क्या केंद्र सरकार का आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में हुए ह्रास की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। इन दरों में जनवरी, 2023 में वेतन और पेंशन के 42% की वृद्धि की गई थी। महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दरें औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर आवधिक रूप से प्रत्येक छह महीने में संशोधित की जाती हैं।

(ग) और (घ): सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****